



क्री क्री आइबैक्स, जिसे क्रीटन गोट, अग्रामी या क्रीटन आइबैक्स भी कहते हैं, जंगली बकरी है, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र के पूर्वी भागों में मिलती है। इस समय ये बकरियाँ सिर्फ यूनान (ग्रीस) में क्रीट के तटवर्ती तीन द्वीपों, डीया, थिओडोरो और अजी पेट्रेस में मिलती हैं। ये सेपिएन्ट्ज़ा द्वीप पर भी देखी जा सकती हैं। विलुपित से बचाने के लिए इस प्रजाति को बड़ी तादाद में इस द्वीप पर लाया गया था। हल्के भूरे रंग की खाल और गर्दन पर गहरे रंग की पट्टी वाले आइबैक्स के विशाल सींग पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। शरीर स्वभाव के ये जीव दिन में आराम करते हैं। ये ना केवल सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ सकते हैं बल्कि छोटी-मोटी छलांग भी लगा लेते हैं। इन्हें क्रीट का मूल वासी नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि, मिनाउन सभ्यता के काल में इन्हें यहां लाया गया था। कभी ये समूचे एजिअन क्षेत्र में बहुत आम थे। लेकिन अब वेस्टर्न क्रीट में वाइट माउन्टेन्स के 2400 मीटर ऊंचे शिखर इनके आखिरी गढ़ हैं। खासकर समारिया गॉर्ज के ऊपर 900 मीटर ऊंचे लगभग सीधे खड़े शिखरों की शृंखला। इस पर्वत शृंखला में 14 और मूल प्रजातियाँ भी मिलती हैं। यह क्षेत्र "यूनेस्को बायोस्फियर रिजर्व" के रूप में रजिस्टर्ड है। हाल ही में दो और द्वीपों पर भी क्री-क्री आइबैक्स को बसाया गया है। बताया जाता है कि, साठ के दशक में क्री क्री भारी खतरे में आ गई थीं। इनकी आबादी मात्र 200 रह गई थी। कारण था कि, दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जब यहां जर्मनी का कब्जा था तब इन पहाड़ियों में छिपे गुरिल्ला लड़ाके भोजन के लिए आइबैक्स का ही शिकार करते थे। आइबैक्स के अस्तित्व पर मंडराता संकट भी एक वजह थी कि, 1962 में समारिया गॉर्ज को नेशनल पार्क बना दिया गया था। क्रीट आइलैंड पर अभी मात्र 2000 आइबैक्स ही हैं और इन्हें "वल्नरेबल" वर्ग में रखा गया है, लेकिन अभी भी इनका शिकार किया जाता है। चारागाहों की कमी, बीमारियों व संकरण के कारण इनके अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। पुरातत्व संबंधी खनन में भी क्री क्री के कई उल्लेख मिलते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि, प्राचीन काल में इस जानवर की पूजा होती थी। क्री क्री को क्रीट आइलैंड का प्रतीक माना जाता है। एक आणविक विश्लेषण से पता चला है कि, यह जंगली बकरी की उपप्रजाति नहीं बल्कि स्वच्छंद रहने वाली डोमैस्टिक गोट है।

मोदी के "युनिफॉर्म सिविल कोड" के नारे का "राजनीतिक" लाभ मिलने लगा

विपक्ष की एकता के प्रयास को कुछ झटका लगा, केजरीवाल ने सशर्त समर्थन दिया नारे को तथा शिव सेना (उद्धव ठाकरे ग्रुप) को भी मुश्किल हो रही है, नारे का विरोध करने में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जून। केन्द्र सरकार के युनिफॉर्म सिविल कोड (यू.सी.सी.) को लाने के प्रयास के चाहे जो अंतिम नतीजे हों, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने का त्वरित लक्ष्य अवश्य पूरा हो गया है

वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले राजनैतिक माहौल में खलबली मचा देना। मोदी ने मंगलवार को यू.सी.सी.

रहे हैं कि वे विपक्षी एकता के लक्ष्य के लिए कदापि शुभ नहीं हैं। पार्टी ने यू.सी.सी. पर सैद्धांतिक समर्थन दिया है और आगामी दिनों में शिव सेना (यू.बी.टी.), जो हमेशा से यू.सी.सी.

दूसरी ओर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व ओवैसी ने कठोर शब्दों में नारे की निंदा की। ओवैसी ने पहले तो हिन्दू संयुक्त परिवार (एच.यू.एफ.) को आयकर में दी गई राहत खत्म करने की मांग की।

मोदी के नारे पर जितनी बहस होती है, उतना ही साम्प्रदायिक धुवीकरण बढ़ता है, जिसका अन्ततोगत्वा राजनीतिक लाभ भाजपा को ही मिलता है।

की जोरदार वकालत की और विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे पर मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं और भड़का रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) से जो संकेत मिल

की समर्थन रही है, के लिए सरकार के इस कदम का विरोध कर पाना मुश्किल होगा। यू.सी.सी., जिसे अल्पसंख्यक मुस्लिमों का विरोधी माना जाता रहा है, पर मुसलमान समुदाय की तरफ से वही

प्रतिक्रिया मिली जिसकी उम्मीद थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई यू.सी.सी. के क्रियान्वयन का राष्ट्रव्यापी विरोध करने का फैसला किया है। इस्लामिक पर्सनल लॉ संगठन ने शरिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। इसे विधि आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा। ए.आई.एम.आई.एम. के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यू.सी.सी. पर प्रधानमंत्री का कदम भारत की विविधता और बहुलवाद पर हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कानून खत्म करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, क्या एच.यू.एफ. को मिलने वाली इनकम टैक्स छूट समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है। एच.यू.एफ. की वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रु. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोलीजियम में दो नए जजों की एंट्री

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जून। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (पी.जे.आई.) डी.वाय. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले 5 जजों के कोलीजियम जस्टिस बी.आर. गवई और सूर्यकांत की पेंद्री होने वाली है, क्योंकि दो वरिष्ठ जज जस्टिस के.एम.

जस्टिस के.एम. जोसफ और जस्टिस अजय रस्तोगी के रिटायर होने की वजह से कोलीजियम में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत को शामिल किया गया है।

जोसफ एवं अजय रस्तोगी क्रमशः 16 व 17 जून को रिटायर हो चुके हैं। नए परिवर्तित कोलीजियम में सी.जे.आई. के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जून। कर्नाटक और खासतौर से तटीय कर्नाटक, जिस तरह से दक्षिण भारत में भाजपा की हिन्दुत्व प्रयोगशाला था, ठीक उसी तरह आज पूरा कर्नाटक राज्य कांग्रेस पार्टी के शासन प्रशासन की प्रयोगशाला बन गया है। और कांग्रेस साहसिक निर्णय लिये जा रही है।

चाहे चुनावी वादों को पूरा करने की बात हो या फिर उपद्रवियों और समाज कंटकों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात हो, कांग्रेस पार्टी जरा भी हिचक नहीं रही है क्योंकि वह जानती है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश-दोनों ही राज्य मिसाल के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले उसके मॉडल है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी जो कर रही है।

मुधवार को कर्नाटक के पार्टी

भाजपा के लिये कर्नाटक का समुद्र तट वाला क्षेत्र हिन्दुत्व की "प्रयोगशाला" थी पूरे दक्षिण भारत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये

- कांग्रेस, कर्नाटक व हिमाचल की सरकारों को लोकसभा चुनाव से पूर्व सुशासन की लैबोरेटरी के रूप में पेश करना चाहती है।
- पर, विचारणीय प्रश्न है, कांग्रेस राजस्थान सरकार को इस मॉडल के रूप में क्यों पेश नहीं कर रही?
- कर्नाटक के मु.मंत्री इस सोच के अंतर्गत, बोम्मई की, "40 प्रतिशत सरकार" के भ्रष्टाचार के मामलों की फाइलें खंगालने लगे हैं, बोम्मई सरकार के भ्रष्टाचार को पूरी तरह उजागर करने के लिये।
- कांग्रेस सरकार ने ईद के मौके पर पुलिस को सख्त हिदायत दी है, शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये और हिन्दुत्व के कट्टरपंथी शरारती तत्वों को कुछ गड़बड़ी फैलाने का मौका नहीं देने के लिये।
- इसी क्रम में सख्ती का उदाहरण पेश करते हुए भाजपा के आई.टी. सैल के मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है, राहुल गांधी के खिलाफ "उत्तेजनात्मक" विडियो जारी करने की घटना में।

नेताओं ने भाजपा आई.टी. सैल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एक

एफ.आई.आर. दर्ज करा दी और इसका कारण था-मालवीय द्वारा कांग्रेस के पूर्व

अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किया गया ट्वीट। अनेक भाजपा नेताओं ने इस

तीखी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने मालवीय के

गुटखा व्यापारी पर जी.एस.टी. की रेड

भोलवाड़ा, 28 जून (नि.स.)। जयपुर जी.एस.टी. विभाग की टीम ने जी.एस.टी. चोरी की लगातार शिकायतें मिलने के बाद बुधवार को भोलवाड़ा के गुटखा व्यापारी रमेश सिंधी के प्रतिष्ठान एवं मकान पर दबिश दी अधिकारियों के

■ भोलवाड़ा निवासी, विमल गुटखा के व्यापारी रमेश सिंधी के घर व दुकान पर आज रेड की गई। कहा जा रहा है कि इसमें जी.एस.टी. की बड़ी चोरी का खुलासा हो सकता है।

मुताबिक यहां से बड़ी जी.एस.टी. राशि चोरी का खुलासा होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक शास्त्री नगर स्थित विमल गुटखा व्यवसाई रमेश सिंधी के दुकान एवं शास्त्री नगर स्थित आवास के साथ ही गोदाम पर जयपुर से आई 6 सदस्य जी.एस.टी. की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से व्यापारी द्वारा जी.एस.टी. चोरी किए जाने की शिकायतें विभाग को मिल रही थीं, जिसके बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बुधवार सुबह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-नेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जून। क्या विपक्षी नेताओं की मीटिंग शिमला को बजाय जयपुर में करने की गंभीर कोशिश हो रही है- ? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश के मौसम में जमीन खिसकने, सड़क अवरूद्ध होने व एयरपोर्ट बंद करने की संभावना हो सकती है, इसलिए इस मौसम में विपक्षी नेताओं को शिमला जाने में दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस के अनुभवी रणनीतिकार चाहते हैं कि यह बैठक कांग्रेस शासित राज्य में हो, चूँकि गर्मी का मौसम है तो हिल स्टेशन से बढ़िया क्या जगह हो सकती है। उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि यह बारिश का मौसम है और सड़कों की हालत खराब होती है। सूत्रों का कहना है कि मामला जब राहुल गांधी के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि मीटिंग कहाँ आयोजित हो इस पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है। यह कहा गया है कि अगर मीटिंग

विपक्ष के नेताओं की बैठक शिमला के बजाय जयपुर में हो सकती है?

कांग्रेस का मानना है कि, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां अगर यह बैठक हो तो, पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है और साथ ही वह राज्य कांग्रेस शासित भी होना चाहिये

■ इस दृष्टि से जयपुर का चयन होने की संभावना है। वैसे भी जिन राज्यों में चुनाव शीघ्र ही अपेक्षित हैं, उनमें कांग्रेस की दृष्टि से राजस्थान सबसे कमजोर माना जाता है।

■ यह मसला, इन तर्कों के साथ राहुल गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, निर्णय लेने के लिये। राजस्थान का विकल्प प्रस्तुत करने वालों को आधी सफलता तो मिल ही गयी अपने प्रयास में, क्योंकि राहुल गांधी ने आयोजन स्थल के चयन पर पुनः विचार की स्वीकृति तो दे दी है।

■ जयपुर का विकल्प प्रस्तुत करने वालों के अन्य तर्क ये हैं कि, भारी बारिश के कारण शिमला के पहाड़ी रास्तों की स्थिति काफी खराब है, साथ ही अति वृष्टि के कारण शिमला का एयरपोर्ट हवाई यात्रा के लिये बंद सा है। बैठक की तारीख आगे भी नहीं खिसकायी जा सकती, क्योंकि ममता बनर्जी 14 जुलाई से 10 दिन के लिये पूर्व निश्चित कार्यक्रमों के कारण "अनुपलब्ध" हैं।

महाधिवेशन हुआ था। अब बचता है सिर्फ राजस्थान और अशोक गहलोत, जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर राजस्थान में है। मीटिंग की तिथि 12 जुलाई है क्योंकि 14 जुलाई के बाद से दस दिन के लिए ममता बनर्जी उपलब्ध नहीं हैं और कई नेताओं को 13 के अंक के प्रति अंध विश्वास है। वे नहीं चाहते इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग 13 जुलाई को हो। केजरीवाल के बैठक में आने की संभावना नहीं है क्योंकि कुछ शर्तों के साथ उन्होंने यूनीफॉर्म सिविल कोड पर मोदी को समर्थन देना आरम्भ कर दिया है। टी.आर.एस. के चंद्रशेखर राव के आने की संभावना भी कम है। वे भाजपा के प्रति नर्मा दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी बेटी की गिरफ्तारी हो जाएगी। एक दिन पहले शिव सेना प्रमुख संजय राजत ने चन्द्रशेखर पर निशाना साधा था और आज बुधवार को शरद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फायदा हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, पर वह भाजपा शासित राज्य है। छत्तीसगढ़ में फरवरी में कांग्रेस का

किसी ऐसे राज्य में होती है जहां चुनाव होने वाले हैं तो इससे पार्टी को फायदा हो सकता है और अगर ऐसा राज्य कांग्रेस शासित हो तो पार्टी को ज्यादा

पायलट व गहलोत आमने-सामने होंगे हाई कमान की बैठक में

शनिवार को आयोजित इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि अन्य वरिष्ठ नेतागण भी भाग लेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जून। कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी की कई बैठकें करने का निर्णय किया है, इसमें उन राज्यों के लिए चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, जहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक बैठक राजस्थान पर भी होगी।

राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को अगले वर्ष अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ चुनावों के बारे में एक मीटिंग बुधवार को हुई थी, जिसमें तय किया गया कि चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम वरिष्ठ नेता शनिवार को राजस्थान के चुनावों की तैयारी से

■ कर्नाटक की भांति, हाई कमान चाहता है कि, दोनों राजस्थान के दोनों नेता, पायलट व गहलोत भी मिल कर चुनाव लड़वायें राजस्थान में।

■ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हाई कमान चुनाव की रणनीति निर्धारण करने के लिये, चार दिन ये बैठकें आयोजित कर रहा है दिल्ली में।

■ छत्तीसगढ़ के चुनाव मसलों के बारे में बैठक बुधवार को हुई थी। इसी क्रम में राजस्थान का नम्बर शनिवार को आयेगा।

संबंधित मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उनके धुर विरोधी सचिन पायलट सहित राजस्थान के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में रहेंगे। इस मीटिंग के बाद गहलोत व पायलट अलग से मीटिंग कर सकते हैं। पार्टी ने नेतृत्व चाहता है कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़े, जैसे कर्नाटक में लड़ा गया था।

इसलिए नेतृत्व गहलोत व पायलट के बीच सुलह करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। नेतृत्व चाहता है कि पायलट ने जो मसले उठाए हैं उनका समाधान हो। कोशिश की गई थी कि पायलट को राजस्थान से हटा दिया जाए, इसके लिए ए.आई.सी.सी. में बड़ा पद देने की बात हुई थी, पर पायलट ने इससे इनकार कर दिया था।

टी.एस. सिंह देव छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सी.एम.

नयी दिल्ली, 28 जून। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह देव को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस महासचिव-संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार देर रात यह जानकारी देते हुए बताया कि, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिंह देव को उप मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया, टी

■ कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणु गोपाल ने देर रात को यह जानकारी दी।

एस सिंह देव छत्तीसगढ़ के नए उपमुख्यमंत्री होंगे। वे कांग्रेस के वफादार नेता और एक कुशल प्रशासक हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से राज्य को बड़ा लाभ होगा। हमें विश्वास है कि, छत्तीसगढ़ की जनता खड़गे जी तथा राहुल गांधी जी के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)